(2) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ रुपये)		योग
	निर्यात	विदेशी मुद्रा के बदले स्थानीय बिक्री	
1989-90 . . .	30.57	9.32	39.89
1990-91 . . .	32.25	40.66*	72.91

*मारुति 1.0 जी.एल.एक्स. के लिए जमा राशियों सहित।

विवरण II

विगत दो वर्षों (1989–90 और 1990–91) के दौरान आयात किए गए मुख्य उपकरणों की सूची ।

1. असेम्बली कन्वेयर
2. ओवर हैड इंजन कन्वेयर
3. व्हाइट बाडी स्टोरेज कन्वेयर
4. पैंटिड बाडी स्टोरेज कन्वेयर
5. डाइयां
6. हाइड्रालिक प्रेसें
7. पेंट लाइन उपकरण
8. वैल्डिंग जिग्स
9. पेंट लाइन के लिए जिग्स एण्ड फिक्सचर्स
10. पोर्टेबल स्पॉट वैल्डर उपकरण
11. पोर्टेबल स्पाट वैल्डर गन्स
12. शटल कन्वेयर
13. ए० सी० चार्जिंग उपकरण
14. टू-इन-टैस्टर

शीर्ष प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

2145. : **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन शीर्ष प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लघु और कृषि उद्योगों के विकास के लिए केंद्र द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या ग्रामीण कारीगरों को सहायता देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य के स्तर पर विशेष विपणन संगठन गठित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र

2146. **श्री ईश दत्त यादव:** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों में ये केंद्र स्थापित नहीं किए जा सके हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन जिलों में यथाशीघ्र जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में 56 केंद्र कार्य कर रहे हैं जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है । नए बनाए गए 7 जिलों अर्थात् कानपुर देहात, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, सोनभद्र, । हरिद्वार और फिरोजाबाद को भी जिला उद्योग केंद्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं । ये 7 जिला उद्योग केंद्र उ० प्र० सरकार, द्वारा स्थापित किए गए हैं और इन्हें वित्तीय बाधाओं तथा योजना आयोग के अनुमोदन के लंबित रहने के कारण केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम के तहत स्थापित नहीं किया जा सका है ।

(ग) सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उ० प्र० के सात जिलों सहित अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिला उद्योग केंद्रों की सूची

क्रम/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जिला उद्योग केन्द्र के नाम

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. एटा
4. मथुरा
5. मैनपुरी
6. इलाहाबाद
7. फतेहपुर
8. प्रतापगढ़
9. कानपुर (नगर)
10. ईटावा
11. फरूखाबाद
12. बरेली
13. बदायूं
14. पीलीभीत
15. शाहजहांपुर
16. फैजाबाद
17. गोंडा
18. बहराइच
19. सुल्तानपुर
20. बाराबंकी
21. गोरखपुर
22. देवरिया
23. आजमगढ़
24. बस्ती
25. झांसी
26. ललितपुर
27. जालोन
28. बांदा
29. हमीरपुर
30. मुरादाबाद
31. रामपुर
32. बिजनौर
33. लखनऊ
34. रायबरेली
35. उन्नाव
36. सीतापुर
37. लखीमपुरखेरी
38. हरदोई
39. मेरठ
40. सहारनपुर

41. मुजफ्फरनगर
42. गाजियाबाद
43. बुलन्दशहर
44. वाराणसी
45. मिर्जापुर
46. जौनपुर
47. गाजीपुर
48. बलिया
49. नैनीताल
50. अल्मोडा
51. पिथौरागढ़
52. पौढी गढ़वाल
53. चमौली
54. उत्तर काशी
55. टिहरी गढ़वाल
56. देहरादून

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नए जिला उद्योग केन्द्रों के नाम जिसके लिए केन्द्र सरकार विकास आयुक्त (ल०उ०) की स्वीकृति लम्बित है

1. कानपुर (देहात)
2. सोनभद्र
3. फिरोजाबाद
4. सिद्धार्थ नगर
5. मऊ
6. हरिद्वार
7. महाराज गंज

औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्र

2147. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पडे हुए आवेदन पत्रों के मामले में लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए लम्बित पडे हुए आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० कुरियन) : (क) से (घ) 1988 से 1991 (नवम्बर, 1991 तक) के दौरान कुल 1672 आवेदन औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे, जिनमें से 666 आवेदनों का अनुमोदन कर दिया गया है और 660 आवेदन नामंजूर कर दिए गए अथवा निपटा दिए गए हैं ।

कोई प्रस्ताव दस वर्षों से अधिक समय से लंबित नहीं है ।

नयी औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं, शेष उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है । औद्योगिक अनुमोदन देने के लिए आवेदनों का निपटान करने की विनिर्दिष्ट समय सीमायें हैं । यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि आवेदनों को इस समय सीमा में निपटा दिया जाए ।

Growth Funds by Small Scale Industr

2148. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the PHD Chambers of Commerce and Industry has recently moote a proposal for creation of Growth Fund